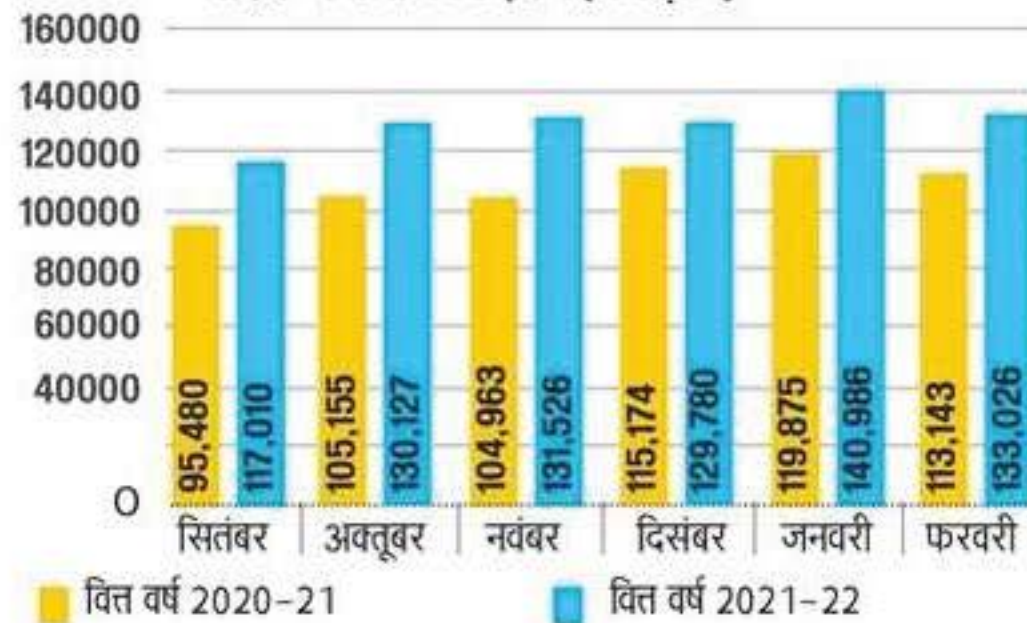


परिषद की बैठक इस महीने के अंत में या अगले महीने के शुरू में हो सकती है जीएसटी की बैठक में तीन कर स्लैब पर विचार संभव

बीते छह माह में जीएसटी संग्रह

संग्रह में तेजी का रुझान (करोड़ में)



07/03/2022

नई दिल्ली। एजेंसी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शीर्ष नीति-निर्धारक इकाई जीएसटी परिषद की अगली बैठक में सबसे निचली कर दर को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत करने पर विचार कर सकती है। जीएसटी परिषद की बैठक इस महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में हो सकती है।

सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति जीएसटी परिषद को इस माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है जिसमें सबसे निचले कर स्लैब को बढ़ाने और स्लैब को तर्कसंगत बनाने जैसे कई कदमों के सुझाव दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, मंत्री समूह कर की दर पांच फीसदी से बढ़ाकर आठ फीसदी करने का प्रस्ताव रख सकता है जिससे सालाना 1.50 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। निचले स्लैब में एक फीसदी की वृद्धि करने पर सालाना 50,000 करोड़ का राजस्व लाभ होगा। मंत्री समूह जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की संख्या कम करने का भी प्रस्ताव देगा। मंत्री समूह की रिपोर्ट पर बैठक में चर्चा की जाएगी। अभी बिना ब्रांड वाले और बिना पैकेज वाले खाद्य पदार्थ और डेयरी वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।

03 स्तरीय कर ढांचा बनाने पर विचार तर्कसंगत प्रणाली के लिए

04 स्तरीय कर ढांचा है अभी मौजूदा वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में

1.5 लाख करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त मिलने की उम्मीद

50 हजार रुपये का लाभ होगा निचली दर में एक फीसदी वृद्धि से

तैयारी

मौजूदा कर प्रणाली

अभी जीएसटी में चार-स्तरीय कर ढांचा है जिसमें कर की दर पांच, 12, 18 और 28 फीसदी है। आवश्यक वस्तुओं को या तो इस कर से छूट प्राप्त है या फिर उन्हें सबसे निचले स्लैब में रखा जाता है जबकि लग्जरी वस्तुओं को सबसे ऊपरी कर स्लैब में रखा जाता है।

संभावित कर प्रणाली

कर प्रणाली को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्री समूह इसका ढांचा तीन स्तरीय करने पर भी विचार कर रहा है जिसमें कर की दर आठ, 18 व 28 रखी जा सकती है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो 12 फीसदी के दायरे में आने वाले सभी उत्पाद एवं सेवाएं 18 फीसदी के स्लैब में आ जाएंगी।